

(ख) इनमें कितने सांसद/विधायक या भूतपूर्व सांसद/भूतपूर्व विधायक हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं तथा उन्हें किन-किन स्थानों पर कारागारों में रखा गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर, 1991 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 148 व्यक्ति जखब थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि नजरबंद किये गये व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति नामतः धर्मपाल यादव, एक भूतपूर्व विधायक (इस समय निर्वाचित विधायक) है। वे डिस्ट्रिक्ट जेल, सुलतानपुर में है।

Criminal gangs operating at Sahar International Airport

1984. SHRIMATI KAMLA SINHA:

DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of criminal gangs are virtually controlling the Sahar International Airport in league with the customs and police officials besides running foreign exchange and emigration racket at the airport thus depriving the exchequer thousands of rupees per day;

(b) if so, whether Government have made any inquiry for identifying the persons involved in the racket and their modus operandi;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) if so, whether Government have made against those found involved in the racket?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Operation Vikram

1985. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government conducted 'Operation Vikram' in Kashmir with a view to flush out the militants, unearth arms and to seal the arms supply routes, in villages around the wuller lake; and

(b) if so, what are the achievements of the operation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) Patrolling of the areas around Wuller Lake to prevent infiltration is regularly done.

In an intensified security force action in mid-October, 1991 in the general area of Wuller Lake, 44 anti-national elements were apprehended, 5 Universal Machine guns, 26 AK rifles, 10 pistols, 2 Radio sets and other arms and ammunition were recovered.

दिल्ली में पकड़े गए अपहरणकर्ता

1986. श्री अजीत जोगी :

श्री बेकल "उत्साही" :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः माह के दौरान राजधानी में कितने अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है;

(ख) कितने मामलों में अपहृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को फिरोती देनी पड़ी है और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी फिरोती देनी पड़ी; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें अपहरणकर्ताओं को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है तथा इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :
(क) 1-1-1991 से 30-11-1991 तक की अवधि के दौरान राजधानी में 311 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि एक मामले में 2 लाख रुपए की फिरौती की राशि दी गई।

(ग) अथक प्रयास करने के बावजूद 191 मामलों में अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ा जा सका।

बिहार में कानून और व्यवस्था

1987. श्री राम अवधेश सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान आज तक अपहरण की सबसे अधिक घटनाएं किस राज्य में हुई हैं; सभी राज्यों में अपहरण, हत्याओं और कमजोर वर्गों की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं का राज्यवार विवरण क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए वहां की सरकार को क्या सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) बिहार सरकार द्वारा मांगे गए और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए आरक्षित पुलिस बल का व्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में दर्ज हुए अपहरण/विपहरण के मामलों की संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना विवरण-I और II में दी गई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अपहरण, हत्या और बलात्कार के मामलों की उपलब्ध सूचना विवरण-III से IV में दी गई है। (कृपया नीचे देखिये)

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" विषय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी, भारत सरकार, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकारों द्वारा जब कभी भी मांग की जाती है तो उन्हें अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) बिहार राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए अर्ध-सैनिक बलों के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न है (विवरण VII)। (कृपया नीचे देखिये)

विवरण I

वर्ष 1990-91 (1.4.90 से 31.3.91) के दौरान दर्ज हुए अपहरण और विपहरण के मामलों की कुल संख्या दर्शाता विवरण।

क्र.सं. राज्य/संघ शासित क्षेत्र

1. आंध्र प्रदेश	890
2. अरुणाचल प्रदेश	52
3. असम	1103
4. बिहार	2282
5. गोवा	23
6. गुजरात	723
7. हरियाणा	250
8. हिमाचल प्रदेश	150
9. जम्मू और कश्मीर	344